भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

१२--१३ जून २०१६, इलाहाबाद

भाजपा नीत एन डी ए सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों पर राजनैतिक प्रस्ताव

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो वर्षों के कार्यकाल में हासिल सफलताओं और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर में केन्द्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी बधाई देती हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था देने और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से प्रारंभ कर, उन्हें पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती है. केन्द्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए, समावेशी विकास के लक्ष्यों, राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों एवं भारतीय जीवन मूल्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति जो सम्मान बढ़ाया है, उसके कारण देश, गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हुआ है.

केन्द्र सरकार ने भारत के विकास के लिए इन दो वर्षों में देश के सामने नई कार्यविधि, पारदर्शी कार्यशैली के नये प्रतिमान रचे हैं. सरकार ने समयबद्ध तरीके से समाज के अंतिम छोर तक, नीतियों के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है. राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में नवाचार इस सरकार की उपलब्धि है. स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, गरीबों में आर्थिक सशक्तिकरण, युवा उत्थान जैसे विषयों पर सरकार की पहल को सामाजिक आंदोलन के रूप में लोगों ने स्वीकार किया है. सुशासन के नये आयामों, नवाचारों एवं सुधारवादी दृष्टिकोण से एक आधुनिक और भविष्योन्मुख भारत की नींव हमारी सरकार और पार्टी ने रखी है.

प्रगति और अवसर के दरवाजे गरीबों के लिए खोले

केन्द्र सरकार ने गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण को दो वर्षों में मिशन मोड में परिवर्तित किया है. आजादी के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबों के लिए 21.81 करोड़ खाते, 31 करोड़ लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 61 हजार 822 करोड़ का सीधा लाभ, मुद्रा योजना में 3 करोड़ 48 लाख लोगों को 1 लाख, 37 हजार, 449 करोड़ रूपये का वितरण सरकार की नई कार्यविधि को दर्शाता है. देश के विकास का प्रत्यक्ष लाभ लोगों तक पहुँचा है और सरकार की विभिन्न सुधारात्मक पहलों के कारण देश में 36 हजार 5 सौ करोड़ रूपये अधिक बचत हुई है.

देश के ग़रीबों को अर्थव्यवस्था और विकास की मुख्य धारा में लाने और उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़े कारक के रूप में 'आधार' क़ानून को लाकर हमने आर्थिक समानता और लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. इस क़ानून से एक तरफ तो फर्जी लाभार्थियों का भ्रष्टाचार और लीकेज बंद हुआ है और दूसरी तरफ, हकदार को उसका हक मिले, इस दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है. प्रगति की धारा में सुधार के लिए मनरेगा और आधार को और सशक्त बनाया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है.

सरकार के समावेशी विकास के इन कदमों का कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. देश में राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता का सार्थक उपयोग नीतियों के निर्माण में हो सकता है परन्तु देश के संसाधनों का उचित वितरण, उसके भ्रष्टाचार एवं लीकेज को रोकने के लिए क्रियान्वयनकारी नीतियों में विपक्ष को क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए. कांग्रेस द्वारा अभी तक जनादेश का सम्मान नहीं किया गया है तथा वामपंथी भी उनके साथ नकारात्मक राजनीति में सक्रिय है.

समृद्ध ग्राम उन्नत भारत

केंद्र सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में किसानों के एवं ग्रामीण क्षेत्र के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त प्रयास किया गया है. विगत दो वर्षों में कम मानसून में भी किसानों को सुरक्षा एवं विश्वास का संबल सरकार द्वारा दिया गया है. कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपया का आवंटन, 1.84 करोड़ मृदा स्वास्थ कार्ड का वितरण, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, सबसे कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभूतपूर्व सुरक्षा, सूखा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित राज्यों को तुरंत राहत की मंजूरी देकर, सरकार ने अर्थव्यवस्था में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है.

देश के ग्रामीण क्षेत्र में 2011-14 के दौरान प्रतिदिन 73.5 किलोमीटर की तुलना में 2015-16 में 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया. आजादी के बाद से आज तक अँधेरे में डूबे गांवों को बिजली पहुंचाकर ग्रामीण जीवन को बदलने का सार्थक प्रयास हुआ है. 2015-16 में 7789 गाँवों में बिजली पहुंचाई गई, जो पिछले 3 सालों की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है. दीनदयाल कौशल योजना में 3.56 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिला है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रम में 19.35 लाख युवा को प्रशिक्षित किया गया है. किसानो को मदद के लिए देश भर में राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास सरकार द्वारा किया जा रहा है. फसल के समय किसानों को मिशन मोड पर नीमकोटेड यूरिया उपलब्ध करवाया गया. देश में पहली बार यूरिया को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ. जो सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

नवाचार

केन्द्र सरकार ने सरकारी रवैये और ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन करने का सफल प्रयत्न किया है. सरकार और सरकारी रवैये के प्रति लोगों की सोच को बदला है. हमने कार्यान्वयन-आधारित नीतियों की शुरुआत की है. हमारी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया है और समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया है. इसके लिए सरकार और आम आदमी के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है. बीच में होने वाली 'लीकेज' को रोका है.

केंद्र सरकार ने राज्यों की राशी में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करके संघवाद को मजबूत किया है. स्थानीय पंचायती राज संस्थानों को पांच प्रतिशत तथा आपदा कोष को प्रभावी करके प्रगतिशील संघवाद की अवधारणा को आगे बढाया है.

यह सरकार, लोगों के मन में, देश के विकास के लिए नई पहल को प्रेरित करने में सफल हुई है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने, अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में, देश के लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की और देखते देखते लगभग एक करोड़ देशवासियों ने अपने आप अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी. यह हमारी सरकार, इसकी नीतियों और नेतृत्व के प्रति, देश की जनता का विश्वास ही है कि इस 'पहल' योजना में लगभग 14000 करोड़ रुपये बचे हैं, जिनसे ग़रीब परिवारों, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में, 'उज्ज्वला' योजना के तहत पाँच करोड़ घरों तक मुफ़्त रसोई गैस पहुँचाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है. पहली बार केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगो पर विशेष नीतियों का निर्माण किया गया है. सरकार उनकी सामाजिक सहभागिता तथा अवसरों की उपलब्धता को आवश्यक मानती है.

देश में मजदूरों के हितों में न्यूनतम पेंशन, यूनिक प्रोविडेंट फंड नंबर, बोनस एक्ट में परिवर्तित तथा सामाजिक सुरक्षा योजना देकर कल्याणकारी राज्य की ओर देशा के कदम बढे है. देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप' योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत देश की प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कम से कम एक महिला को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान है. इस उद्यमिता के संकल्प, से समाज में सभी वर्गों में विकास का भाव जागृत हुआ है.

केंद्र सरकार डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवम्बर संविधान दिवस घोषित किया. डॉ. अम्बेडकर समतामूलक जीवन दर्शन के प्रेरणा हेतु उनसे सम्बंधित पांचों स्थानों को विकसित करने का फैसला लिया है, जो आने वाले समय में नया परिवर्तन लायेगा.

सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की पहल एवं प्रयास द्वारा भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को बराबर एवं अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया है. बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलने के लिए 'बेटी बचाओं-बेटी पढाओं' कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक बेहतर धुआं मुक्त जीवन देने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 91 लाख से अधिक खाते खोले और उनमें 6,510 करोड़ रूपये जमा किये है. 2015-16 में मनरेगा में अब तक सर्वोच्च 55 प्रतिशत महिलाएं है.

सरकार के नवाचार के प्रयोगों से सरलीकृत एमएसएमई पंजीकरण फार्म, आयात और निर्यात के लिए दस्तावेज 7 से घटाकर 3 किये, eBIZसिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाओं से देश में कारोबार करना सुलभ हुआ है. यही कारण है कि विश्व बैंक के 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत अभी तक के अपने उच्चतम स्तर पर है और 2016 में 12 स्थानों का सुधार हुआ है.

पहली बार, भारत सरकार ने युवाओं में नवाचार एवं उद्यमिता के प्रोत्साहन देने के लिए 'स्टार्ट-अप' योजना शुरू की है. इसके अंतर्गत सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर अनुपालन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण, क़ानूनी सहायता, सार्वजनिक खरीद के लिए मानदंडो में छूट तथा पहले तीन वर्षों में आयकर छूट का प्रावधान किया गया है. भारत सरकार ने बी,सी,डी की श्रेणी की सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार की समाप्ति एवं स्वयं सत्यापन को लागु करके देश के युवको को राहत एवं भर्ती में पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है.

देश को 'डिजिटल' बनाने के प्रयास में 'डिजिटल इंडिया' द्वारा शासन पूर्णतः पारदर्शी रह सकेगा. सरकार ने ई-टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का काम किया है. पिछली सरकार में जहाँ घोटालों की बाढ़ आ रखी थी, वहीं हमारी सरकार ने देश का हज़ारों करोड़ रुपया बचाया है. इसी क्रम में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से 3.44 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति सरकार को हुई है.

स्वच्छता एक सामाजिक अभियान

स्वच्छता को एक अभियान से आगे बढ़कर एक मिशन के रूप में इस सरकार ने स्थापित किया है. दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद देश के लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा 42 से बढ़कर 52 प्रतिशत हुआ है. स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय की पहल ने बालिका शिक्षा को संबल प्रदान किया है. स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत का भी आज प्रकटीकरण होने लगा है. यह अभियान देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन का सन्देश लाया है.

महिला सशक्तिकरण

सामाजिक सरोकारों का एक महत्वपूर्ण कदम हमारे समाज में बेटियों के प्रति रवैया बदलने का है. हमारी सरकार ने 'बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ' और सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है. स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो लाख इकसठ हज़ार स्कूलों में चार लाख सत्रह हज़ार से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है. मुद्रा योजना में 79 प्रतिशत से अधिक महिलायें हैं. इसका लाभ महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में भी मिलेगा.

भविष्योंन्मुख भारत

एक आधुनिक एवं भविष्योंन्मुख भारत के निर्माण के लिए दो वर्षों के शासनकाल में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार द्वारा गति दी गई है. माननीय प्रधानमंत्री जी का विकासवादी दृष्टिकोण इसके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है. देश में 2014 में प्रमुख उर्जा संयंत्रों में से एक तिहाई के पास 7 दिनों से भी कम का कोयला स्टॉक था. आज, एक भी बिजली संयंत्र में स्टॉक की स्थिति चिंतनीय नही है. औसत स्टॉक 25 दिनों से अधिक है. पॉवर ग्रिड ने 30,300 करोड़ रूपये लागत की पारेषण परियोजना पारित की है. 2015-16 में 39 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है. भारत दुनिया में स्वच्छ उर्जा की राजधानी बना है. 2015-16 में 3018.80 मेगावाट की सर्वाधिक सौर उर्चा क्षमता में वृद्धि हुई है, जो लक्ष्य से 116 प्रतिशत अधिक है. 2015-16 में 31,472 सौर पंप स्थापित किये गए, जो 1991 से इस कार्यक्रम के शुरुवात के बाद से स्थापित पंम्पो की कुल संख्या से भी अधिक है.

रेलवे सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है. रेलवे में पांच लाख करोड़ का रिकॉर्ड पूंची निवेश हुआ है. 2020 तक उत्तर-पूर्व के सभी राजधानी शहरों को ब्रॉड गेज से जोड़ने की योजना है. एक लाख करोड़ का विशेष रेलवे सुरक्षा कोष का निर्माण किया गया है.

2015-16 में राजमार्गों का 6029 किमी रिकॉर्ड निर्माण किया गया है. 2012-14 में 8.5 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्गों का निर्माण के तुलना में 2015-16 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से निर्माण हो रहा है.

देश में बंदरगाह के आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के तहत 150 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनके बुनियादी ढांचे पर चार लाख करोड़ रूपये निवेश होना है.

बैंकिंग क्षेत्र में सुधर के लिए 'इन्द्रधनुष' फ्रेमवर्क के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सुधार, राष्ट्रीयकरण के बाद सबसे व्यापक सुधार है. बैंकों के कार्यक्षेत्र में राजनीतिक एवं निजी हस्तक्षेप को रोकने के लिए 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' की स्थापना की गई है. सरकार द्वारा नया दिवालिया कानून को पास किया गया है. इससे उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा. कारोबार करने में आसानी तथा साख बाजारों के कार्यकलापों में तेजी से वृद्धि होगी.

सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम, कोल-ब्लाक, खनिज एवं निजी एफएम चैनलों पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया को अपना कर पारदर्शी शासन को मजबूत किया है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन एवं समय पर क्रियान्वयन हेतु प्रगति कार्यसमीक्षा पोर्टल को बढ़ावा दिया गया है. सुशासन में नागरिकों के भागीदारी हेतु mygov.in जैसे अभिनव प्रयोग को शुरू किया गया है और नागरिकों के नीतियों पर सुझाव आमंत्रित किया गया है. बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2017 तक 'भारतीय डाक भुगतान बैंक' स्थापित किये जायेंगे तथा प्रत्येक डाकघर में माइक्रो एटीएम भी होगा.

नई कार्यविधि, नई सोच और उद्देश्यपूर्ण योजनायें हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं. स्वाभिमान, विकास और नवाचार के संकल्प के साथ, भाजपा की यह सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नये, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है.

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक नीति से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है. वैश्विक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों एवं सम्बोधन में भारतीय विचारों एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का दुनिया में सम्मान बढ़ा है. यह उल्लेखनीय है, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमेरिकी कांग्रेस के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डॉ. आंबेडकर के मानवतावादी मूल्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया. भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है. देश में निराशा की जगह आशा और तनाव की जगह शांति का माहौल निर्मित हुआ है. देश का किसान-मज़दूर-ग़रीब आदमी अपने को सुरक्षित और विकास की मुख्य धारा में अनुभव कर रहा है. नौजवानों के अपने पैरों पर खड़े होने की संभावनाओं को नया बल मिला है. केंद्र सरकार की छवि निर्णय लेने वाली, संवेदनशील व पारदर्शी सरकार की बनी है. निश्चित ही, मात्र दो वर्षों में यह एक सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन है.

देश व समाज के बारे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि वे टीम इण्डिया के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों का गरीबो के हितो में प्रभावी क्रियान्वयन करे. भाजपा कार्यकर्ता व समर्थकों से आग्रह है कि वे इस सरकार की पहल व उपलब्धियों की जानकारी घर-घर तक पहुँचाएँ तथा और करने लायक फीडबॅक सरकार के पास पहुँचायें जिससे आगे आनेवाले समय में सरकार और बेहतर करते हुए भारत को नई उँचाइयों पर ले जाने में सफल हो.